के अध्ययन (जैसे - राजनीतिक दल और दबावकारी ग्रुट आदि) पर रुक जाता है। जिनके राज्य के कार्य - कलापों के प्रमुख विभागों के साथ गोचर एवं अगोचर निकट सम्बन्ध होते हैं। इन सबके अलावा, वह एक विशेष तरीके से उन विषयों का भी विवेचना करता है जिनके बारे में अब तक यह समझा जाता था कि वे अर्थशास्त्र, समाजविज्ञान, मनोविज्ञान और नृविज्ञान आदि के क्षेत्र में आते हैं।

जैसा सिडनी वर्बा ने ठीक सुझाव दिया है, "अधिक सैद्धान्तिक ढंग से संगत समस्याओं की वर्णनात्मक रूप में देखो, सरकार की औपचारिक संस्थाओं के परे राजनीतिक परिक्रियाओं और राजनीतिक प्रकाशों को देखो और पश्चिमी यूरोप के देशों के परे एशिया, अफ्रीका और लैटिन - अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखो।

तुलनात्मक शासन से भिन्न, तुलनात्मक राजनीति का अभिप्राय और स्वरूप, इन शब्दों में कार्टिस ने व्यक्त किया है, "तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं के संचालन में सार्थक नियमितताओं, समानताओं और भिन्नताओं से सम्बन्धित है।

इसके सार्थक विश्लेषण के लिए व्याख्यात्मक पूर्व - कल्पनाओं भावनाओं के परीक्षण, आनुभविक सामग्री के संचयन द्वारा कोटिकरण और वर्गीकरण, पक्षेण और प्रयोग आदि की आवश्यकता और अगर सम्भव हो, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अनुसन्धान की तकनीकों जैसे - प्रक्कथन और संचार सामग्री की आवश्यकता पड़ती है।

यद्यपि, कौटिल्य इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि समानताओं और विभिन्नताओं का अन्वेषण, निश्चितता और पूर्वानुमेयता खोज नहीं है: न ही यह इस आधार वाक्य से आरम्भ होता है कि जो विज्ञानसम्मत नहीं है, वह ज्ञान ही नहीं है: नहीं यह इसे व्यवस्थाओं के वर्गीकरण और उनकी श्रेणियाँ सदा सीमा रहित होती हैं। वे यह दावा नहीं कर सकतीं कि ये उनका अन्तिम रूप है और उनमें कोई सुधार नहीं हो सकता। राजनीति के उद्दीपन (Stimuli) के प्रति अनैच्छिक और स्वचालित अनुक्रियाओं की श्रृंखला का स्थान नहीं दिया जा सकता। कई बार अत्यन्त सार्थक राजनीतिक घटनाओं को युगों का मन स्थिति है ऐसे परिवर्तन कहा जा सकता है जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता।

Paper-5 (Chapter-1)

Q. तुलनात्मक राज्यनीति और तुलनात्मक शासन

यद्यपि 'तुलनात्मक राजनीति' और तुलनात्मक सरकार नामक दो पदबन्धों का प्रयोग शिथिल रूप में और एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है दोनों में निश्चित भेद है। जबकि तुलनात्मक सरकार के क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक पद्धतियाँ अपनी विभिन्न संस्थाओं और प्रकार्यों सहित आ जाती है, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। इसमें सामान्य रूप में जो कुछ तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आता है वह तो शामिल है ही, उसके अतिरिक्त वह सब-कुछ भी इसमें शामिल है जिसे 'गैर-राज्य राजनीति (non-State politics) के नाम से अभिहित किया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में, इस बात के बावजूद कि तुलना करने की खोज दोनों के लिए केन्द्र-बिन्दु है, तुलनात्मक सरकार की अपेक्षा तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन अधिक व्यापक है।

तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्थाओं के नियम-निर्माण, नियम-कार्यान्वयन और नियम न्याय-निर्णयन विभागों के अध्ययन तक ही खत्म नहीं हो जाता और न ही उन संविधानेतर अभिकरणों

राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के विभिन्न रूपों के तुलनात्मक अध्ययन से है, परन्तु तुलनात्मक राजनीति शीर्षक के अधीन ऐसे सादृश्यों की ओर संकेत करके उन्हें एक-दूसरे के दूरस्थ देशकाल के राजनीतिक संस्थाओं के बीच दूरवा जा सकता है। हमारा सम्बन्ध संस्थाओं के आवश्यक सादृश्य से है हमें असमानता के प्रासंगिक लक्षणों को आवश्यक समानता के मार्ग का काँटा नहीं बनने देना चाहिए।

Page No.
Date: / /

उपर्युक्त विवेचना से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि 'तुलनात्मक सरकार' के स्थान 'तुलनात्मक राजनीति' पदबन्ध को पसन्द किया जाना व्यापक और विशद है। इसमें वे सभी विशेषताएँ आ जाती हैं जिनका हमने पिछले परिच्छेदों में विवेचन किया है।

हाँ, हम ब्लाण्डेल के इस कथन से सहमत हो सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के समान तभी समझा जा सकता है जब इसके दोनों पहलुओं का विवेचन किया जाए अथवा तुलना में राज्य का उन अन्य संघों और गुटों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है जिनका राजनीतिक स्वरूप और लक्षण होता है और जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

हम ब्लाण्डेल के विचारों से सहमत हैं अथवा नहीं। लेकिन इस सन्दर्भ में यह अवश्य कहा जा सकता है। तुलनात्मक शासन की अपेक्षा 'तुलनात्मक राजनीति' के पदबन्ध को इस्तेमाल करना सर्वत्र अधिक उपयुक्त होगा। शायद इस्टीलर, एडवर्ड फ्रीमैन इन शब्दों में दोनों में अन्तर स्पष्ट करने का प्रयास करते, तुलनात्मक शासन से मेरा अभिप्राय

चाहे वे राष्ट्रीय स्तर पर हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, और चाहे वे विकासशील, राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए हो अथवा विकसित के लिए।

(ii) उसका राजनीतिक व्यवस्था के बने रहने या चलते रहने के मामले से सरोकार है। उसके अनुसार, एक आनुभविक राजनीति वैज्ञानिक का प्रयोजना प्रमुख रूप में उन परिस्थितियों का अध्ययन करना है जिनके अधीन किसी काल या अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं का बनाए रखा जा सकता है।

(iii) वह सन्तुलन-विश्लेषण (equilibrium analysis) की कड़ आलोचना करता है क्योंकि यह उन कारकों विश्लेषण तक सीमित रहता है जो किसी राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व अथवा अस्थायित्व का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते है। अथवा उसका वास्तविक सम्बन्ध उन परिस्थितियों का विवेचना करना है जो किसी राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व और चलते रहने के लिए आवश्यक होती है।

iv) ईस्टन का प्रयोजन राजनीतिक व्यवस्था का सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन करना है। वह लैस्वेल के अनुयायियों की कड़ी आलोचना करता है जो 'सत्ता' के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रायोगिक पक्ष तक सीमित रहते हुए इस विषय के सैद्धान्तिक पक्ष की अवहेलना करते हैं तथा जिनका सम्बन्ध उन परिस्थितियों के अध्ययन से है जो राजनीतिक व्यवस्था के बने रहने के लिए आवश्यक है।

v) अंत में, वह टैलकॉट पार्सन्स जैसे समाज-विज्ञानी के उपागम को अस्वीकार करता है। पार्सन्स ने यह सुझाव दिया था कि राजनीतिक सिद्धान्त का विश्लेषण सामाजिक संस्थाओं के सामान्य सिद्धान्त के शब्दों में किया जा सकता है। ईस्टन का मान्यता के अनुसार, इस प्रकार का दृष्टिकोण राजनीति को समाज विज्ञान की दासी बना देता है।

इस प्रकार उसका प्रयोजन है कि राजनीति के अध्ययन का स्वतन्त्र स्तर पर रखा जाए क्योंकि यह सत्ता के वितरण और इस्तेमाल से प्रभावित मूल्यों के प्राधिकृत विनियान (Authoritative allocation of values) का अध्ययन है।

Q डेविड ईस्टन की विवेचना करे।
(System Analysis of David Easton).

नये राजनीति-विज्ञानियों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम डेविड ईस्टन का है जो व्यवस्था विश्लेषण के उपयोग का अग्रणी समर्थक है 1965 में प्रकाशित उनकी रचना (A system Analysis of political life) को सम-सामयिक अनुभवाश्रित राजनीतिक सिद्धान्त पर अग्रगण्य लेखकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें "सिद्धान्त के स्तर पर विश्लेषण करने एवं नये व सहायक ढंग से राजनीतिक घटना की व्याख्या करने के लिए संकल्पनाओं के एक मूल समुच्चय की व्यवस्था की गई है।" व ईस्टन की आनुभविक राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षण निम्न है -

1) वह राजनीति के एकीकृत सिद्धान्त के पक्ष में है - यह सिद्धान्त राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहार की व्याख्या करने और उनकी तुलना करने में सक्षम है। वह यह बताना चाहता है कि कुछ वर्ग और नियम हर प्रकार की गतिविधियों पर लागू हो सकते है

6. राजनीतिक व्यवस्था सदैव अपने पर्यावरण की चुनौतियों के अधीन रहती है जिनका उसको सामना करना पड़ता है।

7. राजनीतिक व्यवस्था को ऐसी दशा में स्थिति में कहा जाएगा अगर आगतों और निर्गतों के बीच उपयुक्त सन्तुलन बना हुआ है।

ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान

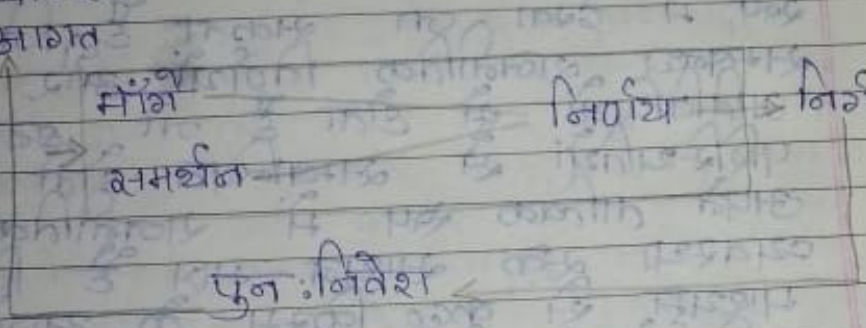

8. प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था क्रान्तिक या संकटग्रस्त क्षेत्र में मौजूद रहता है।

9. राजनीतिक व्यवस्था को बने रहने के लिए किन्हीं संरचनात्मक आवश्कता होती है।

10. राजनीतिक व्यवस्था के समर्थन के तीन तत्व है - राजनीतिक समुदाय, शासन और प्राधिकारीगण।

Page No. 10

राजनीतिक व्यवस्था के सैद्धान्तिक या संकल्पनात्मक और व्यावहारिक या मूर्त पहलुओं के अध्ययन से ईस्टन अपने कई महत्वपूर्ण लेखों में ऐसा व्यवस्थामूलक विश्लेषण पेश करता है जिसके निम्न मुख्य लक्षण हैं:-

1) राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवहार की समग्रता से प्राप्त अतः क्रियाओं का समुच्चय है जिसके माध्यम से समाज के लिए मूल्यों का विनिधान किया जाता है।

2) कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में समान रूप में पाई जाती हैं।

3) ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था एक अचल घटना न होकर एक गत्यात्मक घटना हो जाती है।

4) राजनीतिक व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है जिसमें बाह्य प्रभावों अथवा पर्यावरणीय कारकों से परिवर्तन हो सकता है।

5) राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण समाजान्तरिक और समाजबाह्य दोनों हो सकता है।

12/11/18

Q. ब्रिटिश, फ्रैंच व चीनी एकात्मक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।

Make a comparative analysis of British, french & chinese unitary System.

उ.→ ब्रिटिश एकात्मक व्यवस्था
(British unitary System)

जब सरकार की शक्तियाँ को केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के बीट बाँट दिया जाता है और दोनों के बीच विवादों को तनपटान करने तथा यथा - आवश्यकता संविधान की व्याख्या करने हेतु एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है तो उसे संघात्मक संविधान कहते है। इसके विपरीत, जब सारी शक्तियाँ एक केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती है तो उसे एकात्मक शासन कहते है। यदि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है तो ब्रिटेन अपना एकात्मक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। लन्दन स्थित केन्द्रीय सरकार संवैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च है, जबकी एडिनबरा स्थित स्कॉटलैंड की सरकार, कार्डिक स्थित उत्तरी आयरलैंड की सरकार तथा बेल्फास्ट स्थित वेल्स की सरकार केन्द्रीय सरकार से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है।

11. अपने आप में व्यवस्था होने के साथ राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सी उप-व्यवस्थाएँ होती है, जैसे - मध्यस्था समूह जिसका निर्णय-निर्माण प्रकिया से सम्बन्ध होता है।

इस प्रकार ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा उसके व्यवस्था-मूलक विश्लेषण के समर्थक होने का परिणाम है। उसकी दृष्टि में, राजनीतिक व्यवस्था को बुनियादी तौर पर आगत-निर्गत यन्त्र (input output mechanism) के रूप मे देखा जा सकता है, जिनका सम्बन्ध राजनीतिक निर्णयों और गतिविधियों से होता है जो इन परिस्थितियों से सम्बन्धित होती है। अपने तात्विक रूप में राजनीतिक व्यवस्था एक साधन-मात्र है जिसके माध्यम से कुछ किस्म के आगतों को निर्गतों के रूप मे परिवर्तित किया जाता है।

तथा आन्तरिक विषयों के प्रशासन में उसके उनके पास काफी शक्तियाँ हैं। इस सबके बावजूद ब्रिटिश व्यवस्था एकात्मक है क्योंकि यह सभी स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार की छत्र-छाया के तले है।

प्रांस की एकात्मक व्यवस्था (unitary System of france.)

ब्रिटेन की तरह, फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था है। सारा प्रशासन पेरिस से होता है केन्द्रीय सरकार को शासन की सभी शक्तियाँ प्राप्त है। स्थानीय प्रशासन की खातिर देश मे प्रादेशिक क्षेत्र है जो छोटे-छोटे एककों में बँटे हुए है, किन्तु व केन्द्रीय सरकार के अधीन है, उन्हें स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। संसद के बनाए कानून से ये स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियों प्राप्त करती है। फिर भी इंग्लिश व फ्रेंच व्यवस्थाओं में कुछ अन्तर देखा जा सकता है। यहाँ स्थानीय निकायों पर केन्द्र का नियन्त्रण अधिक कठोर है। गृह विभाग का नियन्त्रण इतना कठोर तथा सर्वव्यापी है कि इतना बटन दबाते हो सारे तार पेरिस से बजने लगते है।"

संघात्मक शासन में इकाइयों की सरकारों को स्वायत्तता प्राप्त होती है, किन्तु एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। यहाँ स्थानीय सरकारें होती है, जैसे - नगरपालिकाएँ या महानगरपालिकाएँ किन्तु वे पत्यक्ष रूप में केन्द्रीय प्रशासन के अधीन होती है।

ब्रिटिश संसद किसी भी स्थानीय निकाय के लिए कानून बना सकती है चाहे वह काउन्टी हो या लन्दन की महानगर परिषद। फिर भी यहाँ शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण के लक्षण देखे जा सकते है। उदाहरण के लिए स्काटलैंड की सरकार के पास अनेक विषयों का प्रबन्धन है, जैसे :-

शिक्षा, कृषि, मत्स्य, गृह तथा स्वास्थ्य तथा यहाँ के सभी संसदों की टोली (स्कॉटिश ग्रैण्ड कमेटी) स्कॉटलैण्ड से सम्बन्धित मामलों पर स्वतंत्र रूप में विचार करती है। उत्तरी आयरलैण्ड में अपनी संसद है जिसमें कॉमन्स सभा व सीनेट नामक दो सदन है।

वहाँ कैबिनेट व गवर्नर - जनरल भी है। ब्रिटिश कैबिनेट में एक मन्त्री वेल्स मामलों के लिए होता है चैनल आइलेण्ड्स तथा आइलैण्ड ऑफ मैन के पास अपनी संसद है

2) प्रान्तों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों के स्वायत्तशासी हल्को (prefectures),

प्रान्तों, स्वायत्तशासी प्रान्तों तथा नगरों में बाँटा गया है।

3) प्रान्तों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों को प्रान्तों को कस्बों तथा राष्ट्रीयताओं के कस्बों में बाँटा गया है। इसके अलावा, प्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार के अधीन नगरपालिकाएँ तथा अन्य बड़े नगर जिलों व प्रान्तों में बँटे है। स्वायत्तशासी हल्कों को प्रान्तो, स्वायत्तशासी प्रान्तों तथा राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्रों में बाँटा गया है। सभी स्वायत्तशासी क्षेत्र, स्वायत्तशासी हल्के तथा स्वायत्तशासी प्रान्त राष्ट्रीय स्वायत्तशासी क्षेत्र है।

संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि चीनी जनगणतंत्र अपनी सारी राष्ट्रीयताओं के लोगों द्वारा सामूहिक तौर से स्थापित एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य है। उनके बीच समानता, एकता तथा परस्पर सहायता के समाजवादी सम्बन्धों को स्थापित किया गया है तथा उन्हें सतत सुदृढ़ किया जाएगा।

चीन की एकात्मक व्यवस्था
(unitary System of china)

यद्यपि चीन बहुत बड़ा राज्य है तथा उसके संविधान ने बहु राष्ट्रीयता के तथ्य को मान्यता दी है, यहाँ एकात्मक व्यवस्था है। शक्तियों का वितरण नहीं है। सारी शक्तियाँ बीजिंग स्थित केन्द्रीय सरकार के पास है। प्रान्तीय, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तरों पर की सभी सरकारें उसी के नियन्त्रणाधीन है। केन्द्रीय सरकार उनके गठन के तरीके तथा उनकी शक्तियों व कार्यों में परिवर्तन कर सकती है। इस समय वहाँ 22 प्रान्त, 5 स्वायत्तशासी क्षेत्र (तिब्बत सहित) तथा 4 नगरपालिकाएँ हैं। हांगकांग तथा मकाओ चीन के विशेष स्वायत्तशासी क्षेत्र है।

1982 के संविधान के अनुसार चीन के जनगणतन्त्र के प्रशासकीय विभाग इस प्रकार है -

1) देश प्रान्तों, स्वायत्तशासी क्षेत्रों तथा नगरपालिकाओं में बंटा है जो प्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार के तले है।

~~Page-1~~

Chapter-5 18

11/11/18

Q British प्रधानमंत्री के युक्ति शक्तियों कार्यों का वर्णन करें।

⇒ यदि राजा राज्य का अध्यक्ष है तो प्रधानमन्त्री को शासन का अध्यक्ष कहा जाता है। यदि कैबिनेट राज्य के जहाज को चलाने वाला यन्त्र है तो प्रधानमन्त्री उस यन्त्र का चालक है। पहले उसे शासन का प्रथम लार्ड कहते थे लेकिन 1937 के ताज के मन्त्रियों के कानून (Minister of the crown act) ने इस पद को वैधानिक मान्यता प्रदान की।

इस कानून में उसके वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख किया गया तथा वरीयता के क्रम में उसे पाँचवाँ स्थान दिया गया है। जब 1714 में जार्ज प्रथम राजा बना जो जर्मन था तथा अंग्रेजी भाषा से अपरिचित था और फिर उसके पुत्र जार्ज द्वितीय की भी यही स्थिति रही तो सारा काम रार्बट वालपोल (Robert Walpole) ने किया और उसी को इंग्लैण्ड का पहला प्रधानमन्त्री होने का श्रेय प्राप्त है।

निष्कर्ष (conclusion)

यद्यपि संघीय तथा एकात्मक व्यवस्थाएँ अपने-अपने गुणों एवं दोषों से युक्त हैं, यहाँ यह कहा जा सकता है कि नवीनतम प्रवृत्ति दोनों का एक न्यायसंगत मिश्रण रखने के पक्ष में है। बहुत से एकात्मक देशों में स्थानीय शासन की इकाइयों को यथासम्भव अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की ओर ध्यान दिया गया है ताकि स्थानीय मामलों का भली प्रकार प्रबन्धन किया जा सके। श्रीलंका का मामला विचित्र है जहाँ द्विप राज्य के उत्तर-पूर्वी भागों में रहने वाले आन्दोलनकारी तमिलों के आन्दोलनों को सन्तुष्ट करने के लिए स्वायत्तता की कुछ मात्रा के साथ प्रान्तीय परिषदों की स्थापना की गई है। प्रत्येक संघीय व्यवस्था में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप इकाइयों ने अपनी स्वायत्तता का काफी अंश खो दिया है जो संघवाद के शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार उनके पास होना चाहिए। केन्द्र की दृढ़ स्थिति की तुलना में इकाइयों की अपेक्षाकृत दुर्बल स्थिति को प्रकट करने के लिए एक नया शब्द अर्द्ध-संघवाद Quasi federalism चलन में आ गयी है।

उदाहरण के लिए, जब 1929 के चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो राजा ने लेबर पार्टी के रैम्जे मैकडोनाल्ड को प्रधानमन्त्री बनाया।

दूसरे महायुद्ध के समय 1940 में राजा ने चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाया जिसने राष्ट्रीय सरकार (National Government) का गठन किया। राजा के ऐसे निर्णय की प्रशंसा की गई।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य लिखित या दस्तावेजी रूप में उपलब्ध नहीं है, वे स्वस्थ परम्पराओं पर आश्रित है। हम उन्हें इस प्रकार इंगित कर सकते है :-

1. प्रधानमन्त्री अपने मन्त्रिपरिषद की महराब की आधारशिला है।

⇒ वह अपने मन्त्रियों का चयन करता है और उनमें विभागों का वितरण करता है। यदि वह किसी मन्त्री से सन्तुष्ट नहीं है, तो उसका त्याग-पत्र माँग सकता है। यदि वह आवश्यक समझे तो मन्त्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है।

2. प्रधानमन्त्री शासन का ही नेता नहीं, वह अपने दल का नेता भी है।

⇒ जब चुनाव होते हैं तो वह टिकट बाँटता है। उसका व्यक्तित्व ही उसके दल की जीत का निर्धारक तत्व होता है।

⇒ प्रधानमन्त्री को पुरस्कार (patronage) का विशाल शक्ति प्राप्त है।

⇒ उसी की सिफारिश पर ताज कार, लार्ड चांसलर, राजदूत तथा अनेक आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्तियाँ होती हैं।

4. प्रधानमन्त्री मुख्य नीति-निर्माता है।

⇒ वह समय-समय पर कैबिनेट की बैठक बुलाता है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं, यदि कोई मन्त्री ऐसे निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे त्याग-पत्र देना चाहिए या प्रधानमन्त्री उससे त्याग-पत्र माँग सकता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री का पद, उसकी शक्तियाँ तथा उसकी प्रभुत्वशाली स्थिति सभी परम्पराओं पर आश्रित है। पूर्व प्रधानमंत्री (Gladstone के ये शब्द महत्वपूर्ण है, "दुनिया में कहीं ऐसा पद नहीं जिसमें इतना सारा भरा हो किन्तु उसका बिम्ब इतना लघु हो, दुनिया में ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जिसके पास इतनी अधिक शक्ति है लेकिन दिखावट में उसके दिखावट में उसके विशेषाधिकार इतने कम है।

राजा प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है। यह पद उसी को दिया जाता है जो कॉमन्स सभा में स्पष्ट बहुमत वाले दल का नेता हो। पहले यही परम्परा थी किसी सांसद को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन जब 1923 में बोनर ला के बाद राजा ने लार्ड कर्जन की जगह स्टेनले बॉल्डविन को प्रधानमन्त्री बनाया तो यह परम्परा पड़ गई कि प्रधानमंत्री कॉमन्स सभा का सदस्य होना चाहिए। यहाँ कारण है कि 1963 में प्रधानमन्त्री बनने से पूर्व लार्ड ह्यूलस होम को अपनी पियरेज छोड़नी पड़ी। किसी अपवादजनक स्थिति में राजा अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

8. प्रधानमंत्री अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

⇒ वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तथा वहाँ लिए गए निर्णयों को अपने देश में लागू करता है।

9. प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र का नेता है।

⇒ यदि कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए तो वह उससे निपटने का हर सम्भव प्रयास करता है।

10. प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने राज्य का नायक है।

⇒ वह अपने सफल कृत्यों से अपने देश का गौरव अर्जित करता है। चैम्बरलेन जैसे अकुशल प्रधानमन्त्री ने दूसरे महायुद्ध को आमंत्रित किया, उसके बाद चर्चिल जैसे कुशल प

5. प्रधानमन्त्री शासन के सामान्य निरीक्षक के रूप में काम करता है तथा सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखता है।

→ यदि कोई विवाद पैदा होता है तो वह उसका समाधान करता है। वह अपने पास कोई विभाग नहीं रखता फिर भी वह किसी विभाग या कर्मचारी के कार्य की देखभाल कर सकता है।

6. प्रधानमन्त्री राजा व अपने मन्त्रियों के बीच सम्पर्क की कड़ी है।

→ वह राजा को अपने मन्त्रियों के विचारों से अवगत करता है। उसी की अनुमति से कोई मन्त्री राजा से भेंट कर सकता है।

7. प्रधानमन्त्री संसद तथा अपने मन्त्रियों के बीच सम्पर्क की कड़ी है।

→ वह अपने मन्त्रियों के परामर्श से संसद का सत्र बुलाने का तारीख निश्चित करता है। यदि संसद में मन्त्रियों पर कड़े प्रहार हो रहे हों तो वह अपना वक्तव्य देकर विरोधी तत्वों को शान्त या संतुष्ट करता है।

संरचना के एक अंग अथवा तत्व की क्रियाएं दूसरे अंग अथवा तत्व पर निर्भर करती है। व्यवस्था की संरचनाओं के अंग, कार्य की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को वे चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो; यदि उन्हें क्रियाशील तन्त्र के रूप में कायम रहना है तो उन्हें एक विशिष्ट प्रकार के कार्य को अवश्य करना पड़ेगा। सतत क्रियाशीलता राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक विशेषता है। ये व्यवस्था की प्रकार्यक आवश्यकताएँ है। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाओं और कभी-कभी उन संरचनाओं के द्वारा, जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाएँ नहीं कहते, किया जाता है। अतः राजनीति व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में न केवल औपचारिक संरचनाओं की तुलना की जानी चाहिए, अपितु उन अनौपचारिक संरचनाओं की भी तुलना करनी चाहिए, जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाओं की श्रेणी में नहीं रखते।

Q. आमण्ड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम करें।

संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक उपागम की दिशा में सबसे योगदान जी. ए. आमण्ड का है। आमण्ड राज्य व्यवस्था के प्रकार्यात्मक सिद्धान्त की तलाश में है। आमण्ड का विश्लेषण संरचनात्मक प्रकार्यिक विज्ञानों विश्लेषण है। इस विश्लेषण पद्धति का सबसे पहले विकास जैविक तथा तांत्रिक विज्ञानों मे हुआ। सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम इसे मानव विज्ञान के अध्ययन में अपनाया गया। बाद में इसे परिष्कृत कर टालकट पारसन्स तथा मेरटिन, लेवी ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक पद्धति के रूप में अपनाया।

इस विश्लेषण पद्धति में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवस्था में संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को पहचाना जा सकता है। इन संरचनाओं के अंग अथवा तत्व व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करते है। व्यवस्था की सक्रियता इनके कार्यों का अर्थ प्रदान करती है अर्थात व्यवस्था की संरचनाओं के अंगो द्वारा किये गये है कार्यों का महत्व व्यवस्था के कार्यों के ही परिप्रेक्ष्य में है।

आमण्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की चार विशेषताएं हैं जिन्हें 'अन्तः क्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान' कहा जाता है —

1) प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएं होती हैं, उनमें से कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण अधिक कार्य कर सकती हैं और अन्य कम विशेषीकृत होने के कारण इससे कम कार्य कर सकती हैं।

2) व्यवस्था और इसकी संरचनाओं में कुछ भी अन्तर हो सकता है, लेकिन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान राजनीतिक कार्य किये जाते हैं।

3) राजनीतिक संरचनाएं कई ऐसे कार्य करती हैं जिन्हें बहुकार्यक कहा जा सकता है।

4) पूर्ण समाज का अंग होने के कारण सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपनी संस्कृति होती है जो कि हमेशा परम्परागत और आधुनिक का मिश्रण होती है।